Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

# डिजिटल भारत और ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

**रविन्द्र सिंह राव***

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) एमएलवी, राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

**शोध सारांश –** भारत एक ग्रामप्रधान देश है जहाँ आज भी लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण समाज भारतीय सामाजिक संरचना की आधारभूत इकाई रहा है। परंपरागत रूप से ग्रामीण जीवन कृषि, जाति व्यवस्था, सामुदायिक संबंधों तथा सीमित संसाधनों पर आधारित रहा है। किन्तु इक्कीसवीं सदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने ग्रामीण जीवन के विविध आयामों को प्रभावित किया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रारम्भ किए गए डिजिटल भारत कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग तथा संचार व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। डिजिटल तकनीकों के प्रसार से ग्रामीण समुदायों की सूचनाओं तक पहुँच बढ़ी है, आर्थिक गतिविधियों में विविधता आई है तथा सामाजिक चेतना के स्तर में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही डिजिटल असमानता, तकनीकी अशिक्षा तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। प्रस्तुत शोध लेख में डिजिटल भारत कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण समाज में हुए सामाजिक परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है।

**शब्द कुंजी –**डिजिटल भारत, ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता, सूचना प्रौद्योगिकी।

**प्रस्तावना –** समाज परिवर्तनशील है तथा परिवर्तन समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों तथा संस्थाओं में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। तकनीकी प्रगति को सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में सम्मिलित किया जाता है।[1]

भारत जैसे विकासशील देश में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साधनों की उपलब्धता ने लोगों के जीवन स्तर, कार्य पद्धतियों तथा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन उत्पन्न किया है।[2]

डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।ङ यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य विद्यमान डिजिटल विभाजन को कम करने का प्रयास करता है।

ग्रामीण भारत लंबे समय तक संचार सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझता रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने इन चुनौतियों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज ग्रामीण नागरिक स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं तथा डिजिटल माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बना रहे हैं।[3]

**डिजिटल भारत की अवधारणा एवं उद्देश्य–** डिजिटल भारत कार्यक्रम का शुभारम्भ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना तथा नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सशक्त करना है।[4]

इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए हैं-

(1) प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटलअवसंरचना की उपलब्धता।

(2) मांग के अनुरूप शासन एवं सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता।

(3) नागरिकों का डिजिटलसशक्तिकरण।

डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं जिनमें भारतनेट, डिजिलॉकर, उमंग पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान तथा ई-हॉस्पिटल परियोजना प्रमुख हैं।[5]

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करना, डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करना तथा सरकारी सेवाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाना है। इसके अतिरिक्त डिजिटलसाक्षरता के माध्यम से नागरिकों को नई तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

**ग्रामीण समाज : अवधारणा एवं विशेषताएँ–** ग्रामीण समाज एक ऐसी सामाजिक इकाई है जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि तथा उससे संबंधित व्यवसायों में संलग्न रहता है। ग्रामीण जीवन की सामाजिक संरचना नगरीय समाज की अपेक्षा अधिक परंपरागत तथा सामुदायिक होती है।[6]

ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. **कृषि आधारित अर्थव्यवस्था–** ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा डेयरी व्यवसाय पर आधारित होती है। किसानों की आय प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है।

2. **प्राथमिक संबंधों की प्रधानता–** ग्रामीण समाज में व्यक्ति–व्यक्ति के बीच प्रत्यक्ष एवं आत्मीय संबंध पाए जाते हैं। परिवार, पड़ोस तथा जातीय समूह सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं।[7]

3. **परंपरागत मूल्यों का प्रभाव–** ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक रीति–रिवाजों तथा सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है।[8]

4. **सीमित संसाधन–** स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग तथा संचार सेवाओं की सीमित उपलब्धता ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न करती रही है। किन्तु डिजिटल तकनीकों के विस्तार ने इन परिस्थितियों में परिवर्तन लाना प्रारम्भ कर दिया है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलअवसंरचना का विकास–** डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलअवसंरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया है। भारतनेट परियोजना के माध्यम से लाखों ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकलफाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।[9]

इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के कारण ग्रामीण नागरिकों को वैश्विक सूचनाओं तक पहुँच प्राप्त होने लगी है। स्मार्टफोन की कीमतों में कमी तथा दूरसंचार सेवाओं के सस्ते होने से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है।[10]

कॉमन सर्विस सेंटरों ने ग्रामीण समाज में डिजिटल परिवर्तन को गति प्रदान की है। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार सेवाएँ, बैंकिंग सुविधाएँ, पेंशन आवेदन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं।[11]

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इससे डिजिटल जागरूकता में वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण नागरिक नई तकनीकों को अपनाने के प्रति अधिक उत्साहित हुए हैं।

**शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन–** डिजिटल तकनीकों के विस्तार ने ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों, पुस्तकालयों तथा अध्ययन सामग्री का अभाव पाया जाता था। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से इन समस्याओं को काफी हद तक दूर किया गया है।[12]

दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, ई–पाठशाला तथा अन्य ऑनलाइन मंचों के माध्यम से विद्यार्थियों को नि:शुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण विद्यार्थियों को महानगरों में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के समान अवसर प्राप्त होने लगे हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बंद होने की स्थिति में मोबाइल फोन, व्हाट्सएप तथा वीडियोकॉन्फ्रेंसिंगप्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षण कार्य संचालित किया गया।[13]

डिजिटल शिक्षा ने विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के तरीकों को बदल दिया है। अब विद्यार्थी ऑनलाइन व्याख्यान सुन सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं।

हालाँकि डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमजोर गति, बिजली आपूर्ति की अनियमितता तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में स्मार्टफोन की अनुपलब्धता शिक्षा के डिजिटलीकरण में बाधा उत्पन्न करती है।

**कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन–** कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। डिजिटल तकनीकों ने कृषि क्षेत्र में आधुनिकता को बढ़ावा दिया है। किसान अब मोबाइल एप्लीकेशनों के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा, उन्नत बीज, उर्वरकों के उपयोग तथा बाजार मूल्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।[14]

ई–नाम प्लेटफॉर्म ने किसानों को राष्ट्रीय स्तर के बाजारों से जोड़ने का कार्य किया है। इसके माध्यम से किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं तथा बिचौलियों पर निर्भरता कम कर सकते हैं।[15]

डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार से किसानों को सरकारी सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होने लगी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका प्रमुख उदाहरण है।[16]

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ई–कॉमर्स गतिविधियों के विस्तार से स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। ग्रामीण युवा ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सेवा केंद्रों तथा फ्रीलांस कार्यों के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं।

**स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल हस्तक्षेप–** ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता लंबे समय से एक गंभीर चुनौती रही है। चिकित्सकों की कमी, स्वास्थ्य केंद्रों की अपर्याप्त संख्या तथा विशेषज्ञ सेवाओं का अभाव ग्रामीण समुदायों के समक्ष प्रमुख समस्याएँ रही हैं। डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण ने इस स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है।[17]

टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों को दूरस्थ स्थानों पर स्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हुई है। इससे यात्रा व्यय और समय दोनों की बचत हुई है। ई–संजीवनी पोर्टल ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को सुदृढ़ किया है।[18]

डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों का सुरक्षित संधारण संभव हो सकेगा।[19]

कोविड–19 महामारी के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्मों की उपयोगिता स्पष्ट रूप से सामने आई। ऑनलाइन पंजीकरण, टीकाकरण प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवाओं ने महामारी नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।[20]

**महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटलसमावेशन–** डिजिटल तकनीक ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। पूर्व में महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से अपेक्षाकृत सीमित अवसरों तक ही पहुँच बना पाती थीं। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों ने उन्हें नई संभावनाओं से परिचित कराया है।

महिलाएँ अब मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन विपणन तथा ई–कॉमर्स गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है।[21]

डिजिटल माध्यमों के द्वारा महिलाएँ सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य

कार्यक्रमों तथा शिक्षा संबंधी सूचनाओं तक आसानी से पहुँच प्राप्त कर रही हैं। इससे उनकी सामाजिक चेतना तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मध्य डिजिटल साक्षरता का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। अनेक परिवारों में महिलाओं को मोबाइल फोन के स्वतंत्र उपयोग की अनुमति नहीं मिल पाती, जिससे डिजिटलसमावेशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है।[22]

**पंचायत राज एवं ई-गवर्नेंस-** डिजिटल भारत कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष ई-गवर्नेंस है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना है।

ई-पंचायत प्रणाली के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कार्यों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। पंचायतों की योजनाएँ, बजट, विकास कार्य तथा वित्तीय विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।[23]

ग्रामीण नागरिक अब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं में भी कमी आई है।

डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने पंचायत स्तर पर वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाया है। मनरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है।

ई-गवर्नेंस ने प्रशासन और नागरिकों के मध्य संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाया है तथा शासन व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास में वृद्धि की है।

**सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन-** डिजिटल तकनीकों ने ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने ग्रामीण समुदायों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर जोड़ने का कार्य किया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब तथा इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों के द्वारा लोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, विचारों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं।[24]

डिजिटल संचार के कारण पारंपरिक सामाजिक संबंधों में परिवर्तन देखा जा रहा है। जहाँ पूर्व में सामूहिक बैठकों तथा व्यक्तिगत संवादों का महत्व अधिक था, वहीं अब डिजिटल संचार माध्यमों के उपयोग में वृद्धि हुई है।

ग्रामीण युवाओं की जीवन शैली, पहनावा, उपभोग संबंधी आदतें तथा कैरियर संबंधी आकांक्षाएँ भी डिजिटल संस्कृति से प्रभावित हुई हैं। वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण ने ग्रामीण एवं शहरी जीवन के मध्य की दूरी को कम करने का कार्य किया है।

हालाँकि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। अफवाहों का प्रसार, साइबर अपराध, सामाजिक तनाव तथा सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण जैसी समस्याएँ भी डिजिटल विस्तार के साथ उभरकर सामने आई हैं।[25]

**डिजिटल भारत कार्यक्रम की चुनौतियाँ-** डिजिटल भारत कार्यक्रम की उपलब्धियों के बावजूद अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

1. **डिजिटल विभाजन-** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य इंटरनेट की उपलब्धता तथा उपयोग के स्तर में अभी भी पर्याप्त अंतर विद्यमान है।
2. **डिजिटल अशिक्षा -** ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग आधुनिक डिजिटल उपकरणों के उपयोग में दक्ष नहीं है।
3. **तकनीकी अवसंरचना का अभाव-** कई दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है तथा बिजली आपूर्ति भी नियमित नहीं रहती।
4. **साइबर सुरक्षा संबंधी समस्याएँ-** ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकिंग फ्रॉड तथा व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी जैसी समस्याएँ डिजिटल विस्तार के साथ बढ़ी हैं।
5. **आर्थिक असमानता-** आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का नियमित उपयोग अभी भी चुनौतीपूर्ण है।

**निष्कर्ष -** डिजिटल भारत कार्यक्रम ने ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण समुदायों को नई सूचनाओं, अवसरों तथा संसाधनों तक पहुँच प्रदान की है।

महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय में वृद्धि, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में डिजिटल भारत कार्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसके बावजूद डिजिटल विभाजन, तकनीकी अशिक्षा तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

यदि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सेवाएँ, डिजिटल प्रशिक्षण तथा तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तो डिजिटल भारत कार्यक्रम सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा ग्रामीण परिवर्तन के प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित हो सकता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. आर. एम. मैकाइवर एवं चार्ल्सएच. पेज, समाज (Society), मैकमिलन प्रकाशन, न्यूयॉर्क, 1961।
2. एम. एन. श्रीनिवास, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन (Social Change in Modern India), ओरिएंटलॉन्गमैन, नई दिल्ली, 1995।
3. भारत सरकार, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme), नई दिल्ली, 2015।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), डिजिटल इंडिया वार्षिक प्रतिवेदन2023-24, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार, प्रेस विज्ञप्ति, 1 जुलाई 2015।
6. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन2024, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. ए. आर. देसाई, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र (Rural Sociology in India), पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई, 2012।
8. डी. एन. मजूमदार, ग्रामीण रूपरेखाएँ (Rural Profiles), एशिया पब्लिशिंग हाउस, बंबई, 1958।
9. दूरसंचार विभाग, भारतनेट परियोजना प्रतिवेदन2024 (BharatNet Project Report), भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI), दूरसंचार सदस्यता प्रतिवेदन2024 (Telecom Subscription Report), नई दिल्ली।
11. सीएससी ई-गवर्नेंससर्विसेज इंडिया लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन2024, नई दिल्ली।
12. शिक्षा मंत्रालय, डिजिटल शिक्षा पहल (Digital Education

Initiatives), भारत सरकार, नई दिल्ली, 2023।
13. यूनेस्को, कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा (Education During COVID-19 Pandemic), पेरिस, 2021।
14. कृषि मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन2024, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. ई-नाम पोर्टल (e-NAM Portal), भारत सरकार, 2024।
16. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिशा-निर्देश (PM-KISAN Scheme Guidelines), भारत सरकार, 2024।
17. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन2024, भारत सरकार, नई दिल्ली।
18. ई-संजीवनी टेलीमेडिसिनप्रतिवेदन2024 (eSanjeevani Telemedicine Report), भारत सरकार, 2024।
19. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन दस्तावेज (National Digital Health Mission Documents), भारत सरकार, 2024।
20. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), भारत में कोविड-19 के प्रति प्रतिक्रिया (COVID-19 Response in India), जिनेवा, 2022।
21. नाबार्ड, स्वयं सहायता समूह एवं डिजिटलसमावेशन (SHGs and Digital Inclusion), मुंबई, 2023।
22. संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women), भारत प्रतिवेदन2023 (UN Women India Report), 2023।
23. पंचायती राज मंत्रालय, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (e-Panchayat Mission Mode Project), भारत सरकार, नई दिल्ली, 2024।
24. मैनुअलकैस्टेल्स, नेटवर्क समाज का उदय (The Rise of the Network Society), वाइली-ब्लैकवेल प्रकाशन, 2010।
25. एंथनीगिडेन्स, समाजशास्त्र (Sociology), पॉलिटी प्रेस, लंदन, 2013।

**********